



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन  
अधिनियम, 2003 के अनुपालन  
पर  
वर्ष 2021-22 के लिए प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार  
आर्थिक कार्य विभाग  
(वित्त मंत्रालय)  
2024 की प्रतिवेदन संख्या 1



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का  
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन  
अधिनियम, 2003 के अनुपालन  
पर  
वर्ष 2021-22 के लिए प्रतिवेदन

संघ सरकार  
आर्थिक कार्य विभाग  
(वित्त मंत्रालय)  
2024 की प्रतिवेदन संख्या 1



## विषय-सूची

शीर्षक	पृष्ठ सं
प्रस्तावना	iii
कार्यकारी सार	v
अध्याय 1: परिचय	1
अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियाँ	7
अध्याय 3: प्रकटीकरण और पारदर्शिता	27
अनुलग्नक	33
शब्दकोष	41



## प्रस्तावना

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 की धारा 7ए के तहत बनाए गए नियम 8 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) को एफआरबीएम अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुपालन की समय-समय पर समीक्षा करने और वित्तीय वर्ष 2014-15 से संसद के दोनों सदनों के समक्ष ऐसी समीक्षा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संघ सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन पर सीएजी का यह सातवीं प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन एफआरबीएम लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों और प्रकटीकरण विवरणों में जानकारी की पर्याप्तता की जांच करती है और राजकोषीय नीति विवरणों में किए गए अनुमानों के साथ वास्तविक की तुलना करती है।

प्रतिवेदन में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो 2021-22 के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। जहां भी प्रासंगिक हो वहाँ, 2021-22 से पहले की अवधि से संबंधित मामले, जिनका राजकोषीय संकेतकों पर असर पड़ता है, को भी शामिल किया गया है।



## कार्यकारी सार

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, अधिनियम (एफआरबीएम) 2003 को राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जुलाई 2004 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय स्थिति और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय घाटे (एफडी) की सीमा निर्धारित करना था (क्योंकि वर्तमान उधार का बोझ भविष्य में उठाना होगा)।

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 का नियम 8 सीएजी द्वारा अधिनियम के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा निर्धारित करता है और वर्तमान प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 के लिए किए गए निष्कर्षों पर चर्चा करती है।

किसी सरकार की राजकोषीय स्थिति के प्रमुख संकेतकों में से एक एफडी है, जो अपने स्वयं के राजस्व संसाधनों और व्यय (उधार/ऋण को छोड़कर) के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार की उधारी को शामिल करता है। कुल मिलाकर लक्ष्य एक वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत तक सीमित रखना था। इस गिरावट को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया; इसलिए, वर्ष 2021-22 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। हालाँकि, सरकार ने राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग को आगे बढ़ाने और वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया।

हमने देखा कि सरकार कोविड के वर्षों से उबरकर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की राह पर वापस आ गई है। ऋण स्थिरता संकेतक द्वारा मापी गई ऋण स्थिरता, 2021-22 में सकारात्मक हो गई। 2021-22 के अंत में केंद्र सरकार का कर्ज घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 58.59 प्रतिशत हो गया जो कि 2024-25 के अंत में अधिनियम में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले है। सामान्य सरकारी ऋण, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के ऋण को जोड़ता है, 2020-21 की तुलना में घट रहा था और 2021-22 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद का 82.63 प्रतिशत था, जबकि 2024-25 के अंत में 60 प्रतिशत का लक्ष्य है।

सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण पर दी गई सरकारी गारंटी को वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत की लक्ष्य सीमा के भीतर बनाए रखा गया था। हमने गारंटियों के संबंध में प्रकटीकरणों में कमी देखी। अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर - केंद्र सरकार के ऋण का एक घटक होने के नाते) के प्रकटीकरण में भी पूर्णता के संबंध में कमी पाई।

अध्याय

1

परिचय



अध्याय	परिचय
1	

### 1.1 एफआरबीएम अधिनियम

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियम और अधिनियम के तहत नियम 05 जुलाई 2004 को लागू किए गए थे। 2003 में मूल अधिनियम के अधिनियमन के बाद से, इसे 2004, 2012, 2015 और 2018 में चार बार संशोधित किया गया है। अधिनियम और नियमों में प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक 1.1 में दी गई हैं। अधिनियम का उद्देश्य दीर्घकालिक व्यापक-आर्थिक स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी<sup>1</sup> सुनिश्चित करना है। एफआरबीएम संशोधन अधिनियम, 2018 में निर्धारित और वर्ष 2021-22 के लिए लागू लक्ष्य इस प्रकार हैं:

केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक यह सुनिश्चित करेगी कि:

- ❖ सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 60 प्रतिशत से अधिक न हो।

[धारा 4(1)]

"सामान्य सरकारी ऋण" को अंतर-सरकारी<sup>2</sup> दायित्वों को छोड़कर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों<sup>3</sup> के ऋण की कुल राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

- ❖ केंद्र सरकार का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो।

[धारा 4(1)]

<sup>1</sup> अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी एक सिद्धांत है जो आज की पीढ़ी की अल्पकालिक जरूरतों को भविष्य की पीढ़ियों की दीर्घकालिक जरूरतों के साथ संतुलित करता है।

<sup>2</sup> जिस राशि से राज्य और संघ एक-दूसरे के ऋणी हैं।

<sup>3</sup> भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत, "कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है यदि भारत सरकार द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है या उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा या जिसके संबंध में भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गारंटी दी गई है।" तदनुसार, भारत सरकार निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य सरकार के लिए उधार की वार्षिक सीमा निर्धारित करती है।

- ❖ किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी **सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक** न दे।

[धारा 4(1)]

- ❖ वित्त मंत्री अर्ध-वार्षिक आधार पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के परिणाम को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे।

[धारा 7(1)]

- ❖ यदि अर्धवार्षिक समीक्षा (अर्थात् सितंबर के अंत) के परिणाम से पता चलता है कि (i) कुल गैर-ऋण प्राप्तियां बजट अनुमान (बीई) के 40 प्रतिशत से कम हैं, और (ii) राजस्व घाटा (आरडी)<sup>4</sup> और राजकोषीय घाटा (एफडी)<sup>5</sup> वर्ष के लिए बीई के 70 प्रतिशत से अधिक हैं, तो वित्त मंत्री पहली छमाही के अंत के तुरंत बाद वाले सत्र के दौरान संसद में एक विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण दिया जाएगा।

[नियम 7]

वर्ष 2021-22 के लिए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक मध्य-वर्ष (अर्थात् सितंबर के अंत) की समीक्षा प्रस्तुत की गई, जिसके परिणाम एफआरबीएम नियमों के तहत निर्धारित अनिवार्य मध्य-वर्ष बेंचमार्क के अनुपालन में थे। विस्तृत परिणाम **अनुलग्नक-1.2** में दिया गया है।

- ❖ केंद्र सरकार 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक कम कर देगी। हालाँकि, अधिनियम में किसी और संशोधन के न होने से, सरकार **वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम** राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन का एक व्यापक मार्ग अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में बताया गया है और 2022-23 के लिए एमटीएफपी विवरण में दोहराया गया है।

<sup>4</sup> "राजस्व घाटा" का अर्थ राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर है।

<sup>5</sup> "राजकोषीय घाटा" का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों और ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर, भारत की समेकित निधि से निधि में कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल संवितरण की अधिकता।

## 1.2 एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित अन्य दायित्व

केंद्र सरकार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी :

- ❖ मध्यम-अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति (एमटीएफपी सह एफपी) विवरण (फॉर्म एफ1 में):

*इस विवरण में राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य शामिल है अर्थात् राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा<sup>6</sup>, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, कर राजस्व और केंद्र सरकार का ऋण। इसमें अंतर्निहित धारणाएँ भी शामिल हैं।*

- ❖ वृहत आर्थिक ढांचा विवरण (फॉर्म एफ 2 में) - एमईएफ विवरण:

*अंतर्निहित धारणाओं के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में विकास के साथ बजट की परस्पर क्रिया पर प्रकाश डाला गया है।*

- ❖ मध्यम अवधि व्यय ढांचा (एमटीईएफ) विवरण (फॉर्म एफ 3 में):

*यह विवरण (निर्धारित फॉर्म एफ3 में) अंतर्निहित मान्यताओं और जोखिमों के साथ निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य प्रदान करता है। 2018-19 को छोड़कर, सरकार इस विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रही है। इस तथ्य को सरकार ने एमटीएफपी 2022-23 में स्वीकार किया था, हालांकि कोई कारण नहीं बताया गया था।*

[धारा 3(1)]

- केंद्र सरकार कुछ<sup>8</sup> परिस्थितियों को छोड़कर रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी।

[धारा 5(1)]

- केंद्र सरकार अपने खातों का मासिक विवरण तैयार करेगी।

[धारा 7(1ए)]

<sup>6</sup> "प्राथमिक घाटा" का अर्थ है राजकोषीय घाटा घटा ब्याज भुगतान।

<sup>7</sup> इसमें राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित स्थिरता का आकलन भी शामिल है; उत्पादक परिसंपत्तियाँ उत्पन्न करने के लिए बाजार उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग।

<sup>8</sup> नकद प्राप्ति, प्राथमिक मुद्रों की सदस्यता और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा आदि के आधार पर नकद संवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करने के लिए, और द्वितीयक बाजार में खुले बाजार संचालन को पूरा करने के लिए।

- नियमों में निर्धारित किए गए पांच प्रकटीकरण फॉर्म (डी-1 से डी-5)<sup>9</sup> कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, गारंटी, परिसंपत्ति रजिस्टर और वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता बजट के साथ संसद में रखे जाने चाहिए।

[नियम 6]

### 1.3 लेखापरीक्षा का दायरा और अधिदेश

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के नियम 8 के साथ पठित धारा 7ए<sup>10</sup> (2018 संशोधन अधिनियम) के अनुसार, भारत के सीएजी को वित्तीय वर्ष 2014-15 से, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। समीक्षा में शामिल होंगे:

- अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की उपलब्धि और अनुपालन का विश्लेषण, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, वृहद्-आर्थिक रूपरेखा विवरण और मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा विवरण।
- अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और व्यापक-आर्थिक मापदंडों के रुझान का विश्लेषण।
- अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि पर असर डालने वाले राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों या दायित्वों के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियाँ।
- अपने राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रकटीकरण का विश्लेषण।

<sup>9</sup> प्रकटीकरण प्रपत्र (डी1) - कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया, (डी2) - गैर-कर राजस्व का बकाया, (डी3) - सरकार द्वारा दी गई गारंटी, (डी4) - संपत्ति रजिस्टर और (डी5) - वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता। ये खुलासे डेटा प्रदान करते हैं जो वित्त लेखों (नकदी के आधार पर तैयार किए जाने वाले) में शामिल नहीं होते हैं लेकिन राजकोषीय संकेतकों के लिए प्रासंगिक होते हैं।

<sup>10</sup> एफआरबीएम समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना - केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समय-समय पर समीक्षा करने का काम सौंप सकती है और ऐसी समीक्षाएं संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी।

तदनुसार, सीएजी ने छह (6) प्रतिवेदन तैयार की हैं (तालिका 1.1)

**तालिका 1.1: संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई सीएजी प्रतिवेदन**

क्र.सं.	सीएजी प्रतिवेदन	वित्तीय वर्ष जिससे प्रतिवेदन संबंधित है
1	2016 की प्रतिवेदन संख्या 27	2014-15
2	2017 की प्रतिवेदन संख्या 32	2015-16
3	2018 की प्रतिवेदन संख्या 20	2016-17
4	2021 की प्रतिवेदन संख्या 06	2017-19
5	2022 की प्रतिवेदन संख्या 18	2019-20
6	2022 की प्रतिवेदन संख्या 32	2020-21

#### 1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

समीक्षा मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में की गई, जो एफआरबीएम अधिनियम के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है। प्रतिवेदन केंद्र सरकार के वित्त खातों (यूजीएफए) 2021-22 और 2019-20 से 2023-24 के क्रमिक बजट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी पीएसई और जीडीपी डेटा के प्रमाणित वार्षिक खातों का उपयोग विश्लेषण के लिए किया गया है।

मसौदा प्रतिवेदन 10 जुलाई 2023 और 12 सितंबर 2023 को वित्त मंत्रालय को जारी की गई थी। 19 जुलाई 2023 को मंत्रालय के साथ एक निकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्तमान प्रतिवेदन में मंत्रालय से दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को प्राप्त लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

#### 1.5 आभार

हम रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और इस अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन को सुविधाजनक बनाने में आर्थिक कार्य विभाग के सहयोग के लिए आभारी हैं।

## 1.6 प्रतिवेदन की संरचना

वर्तमान प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए एफआरबीएम (संशोधन) नियम 2018 के नियम 8 के अनुसार भारत के सीएजी द्वारा वार्षिक समीक्षा है।

अध्याय 1 एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के लिए अधिदेश पर चर्चा करता है, जबकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अगले **अध्याय 2 और 3** में चर्चा की गई है।

अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियाँ।

अध्याय 3: प्रकटीकरण और पारदर्शिता।

## अध्याय 2

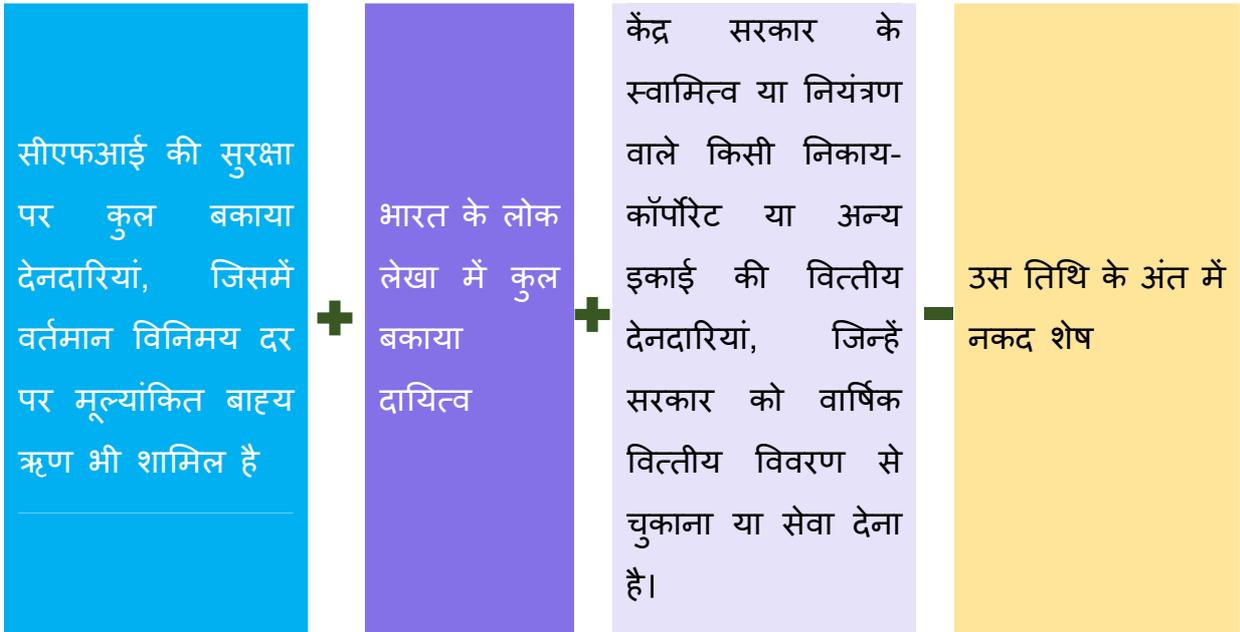
एफआरबीएम लक्ष्य और  
उपलब्धियाँ



अध्याय	एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियां
2	

### 2.1 केंद्र सरकार ऋण और सामान्य सरकारी ऋण

2018 में संशोधित एफआरबीएम अधिनियम ने एक नई धारा 2(एए) प्रस्तुत की, जो किसी भी तारीख पर केंद्र सरकार के ऋण की अवधारणा को परिभाषित करती है, जिसमें शामिल हैं:



इसी प्रकार, धारा 2(बीबी) "अंतर-सरकारी दायित्वों को शामिल न करके, सामान्य सरकारी ऋण को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऋण का कुल योग" के रूप में परिभाषित करती है। एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक सीमित करना है।

#### 2.1.1 केंद्र सरकार का बकाया ऋण

पांच वर्ष की अवधि 2017-2022 (तालिका 2.1) के विश्लेषण से पता चला है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में लगातार बढ़ते हुये 61.55 प्रतिशत हो गया और बाद में 2021-22 के अंत में गिरकर 58.59 प्रतिशत

हो गया। पूर्ण रूप से ऋण में वृद्धि, 2021-22 में ₹16.78 लाख करोड़ या 2020-21 की तुलना में 13.78 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्य रूप से आंतरिक ऋण में ₹15.52 लाख करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, साथ ही इस अवधि के दौरान लोक लेखा देनदारी में ₹1.17 लाख करोड़ की कमी आई।

**तालिका 2.1: केंद्र सरकार का बकाया ऋण**

(₹ लाख करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आंतरिक ऋण	वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण	लोक लेखा दायित्व <sup>11</sup>	अतिरिक्त बजटीय संसाधन <sup>12</sup>	नकदी शेष <sup>13</sup>	केंद्र सरकार का ऋण	वर्तमान कीमतों पर जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण
	1	2	3	4	5	6 (1+2+3+4-5)	7	8= (6/7x100)
2017-18	64.01	4.45	16.47	*	*	84.94	170.90	49.70
2018-19	70.75	4.74	18.12	0.90	1.25	93.26	189.00	49.34
2019-20	80.20	5.44	18.79	1.12	0.48	105.07	200.75	52.34
2020-21	99.10	6.15	17.61	1.39	2.38	121.87	198.01	61.55
2021-22	114.62	6.58	16.44	1.39	0.38	138.65	236.65	58.59

स्रोत: आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण और लोक लेखा दायित्वों के लिए संबंधित वर्षों के यूजीएफए का संदर्भ लें। अतिरिक्त बजटीय संसाधन (सकल) 2019-20 से 2023-24 के बजट दस्तावेजों में व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 के अनुसार हैं। जीडीपी डेटा के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की 31 जनवरी 2022 और 06 जनवरी 2023 की प्रेस विज्ञप्तियां देखें।

\*ईबीआर और नकदी शेष के घटकों के साथ केंद्र सरकार के ऋण की परिभाषा को अप्रैल 2018 में एफआरबीएम संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था।

<sup>11</sup> इसमें आरक्षित निधि और जमा सहित लघु बचत और भविष्य निधि पर देयता शामिल है। वर्ष 2021-22 के लिए ये राशि क्रमशः ₹12.24 लाख करोड़ और ₹4.20 लाख करोड़ थी। इसके अलावा, छोटी बचत पर देनदारी में 2021-22 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को दिए गए ₹570 करोड़ का ऋण भी शामिल था, हालांकि, विवरण का प्रकटीकरण व्यय प्रोफाइल 2023-24 के विवरण 27 के एक भाग के रूप में नहीं किया गया था, जिसमें 'एनएसएसएफ से ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता' दिखाई गई थी।

<sup>12</sup> जैसा कि बाद में पैरा 2.3 में बताया गया, 2020-21 और 2021-22 के लिए सकल ईबीआर ₹9 करोड़ से अधिक बताया गया था, और ईबीआर चुकाए जाने की राशि का पूरा विवरण अभी भी मंत्रालय से प्रतीक्षित था (फरवरी 2024)। इस प्रकार, ईबीआर आंकड़े सकल मूल्य पर उल्लिखित हैं।

<sup>13</sup> 2018-19 से 2020-21 के लिए नकद शेष के आंकड़ों में संघ सरकार के वित्त खाते मुख्य शीर्ष 8673 - नकद निवेश खाते और मुख्य शीर्ष 8999 - नकद शेष के अनुसार है।

मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण 2023-24 (फरवरी 2023) में, सरकार ने कहा कि उसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 58.8 प्रतिशत से घटाकर आरई 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 57.0 प्रतिशत करने की योजना बनाई है। प्राप्ति बजट 2023-24 में केंद्र सरकार की कुल देनदारियां ₹135.67 लाख करोड़ बताई गईं। एफआरबीएम अधिनियम 2003 (2018 में संशोधित) में दी गई परिभाषा के आधार पर हमारी गणना ₹138.65 लाख करोड़ थी। अंतर का मिलान नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है:

**तालिका 2.2: 2021-22 के अंत में केंद्र सरकार की दायित्वों का प्राप्ति बजट 2023-24 में किया गया प्रकटीकरण**

(₹ लाख करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्राप्ति बजट 2023-24	एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार लेखापरीक्षा में गणना की गई
1	आंतरिक ऋण	114.62	114.62
2	बाह्य ऋण	4.39 (बुक वैल्यू पर)	6.58 (वर्तमान विनिमय दर पर)
3	अन्य दायित्व/लोक लेखा दायित्व	16.65	16.44
4	ईबीआर	शामिल नहीं	1.39
5	नकद शेष	शामिल नहीं	0.38
6	केंद्र सरकार का ऋण	135.67	138.65

2010-11 से, केंद्र सरकार ने सरकारी ऋण पर एक वार्षिक स्थिति पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष के अंत में केंद्र सरकार के ऋण के आंकड़ों की गणना की गई है। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (अक्टूबर 2023) कि "2021-22 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र को मंजूरी दे दी गई है और प्रकाशन के अंतिम चरण में है"। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2021-22 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र 23 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुआ।

## 2.1.2 सामान्य सरकारी ऋण

स्थिति पत्र (23 अक्टूबर 2023) से निकाला गया सामान्य सरकारी ऋण नीचे तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3: सामान्य सरकारी ऋण

(₹ लाख करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	सामान्य सरकारी ऋण/दायित्व	119.36	133.03	150.99	174.07	195.54
2	केंद्र सरकार का ऋण <sup>14</sup>	84.94	93.26	105.07	121.87	138.65
3	सकल घरेलू उत्पाद	170.90	189.00	200.75	198.01	236.65
4	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामान्य सरकारी ऋण/ दायित्व	69.84	70.39	75.21	87.91	82.63
5	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण	49.70	49.34	52.34	61.55	58.59
6 = (4-5)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में विशेष रूप से राज्य सरकार के ऋणों पर अतिरिक्त दायित्व,	20.14	21.05	22.87	26.36	24.04

स्रोत: जीडीपी डेटा के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की 31 जनवरी 2022 और 06 जनवरी 2023 की प्रेस विज्ञप्तियां देखें।

सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त सामान्य सरकारी ऋण/दायित्व 2020-21 में महामारी वर्ष के दौरान 87.91 प्रतिशत का सर्वकालिक उच्च दर्ज करने के बाद, 2017-18 में 69.84 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 82.63 प्रतिशत हो गई (तालिका 2.3)। 2018 में संशोधित एफआरबीएम अधिनियम 2003 द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत तक सीमित करना है।

<sup>14</sup> 2018 तक संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में दी गई केंद्र सरकार के ऋण की परिभाषा के अनुसार, 2021-22 के लिए सरकारी ऋण की स्थिति पत्र में उल्लिखित पाकिस्तान पूर्व विभाजन ऋण से संबंधित राशि को केंद्र सरकार की ऋण की गणना के लिए नहीं माना गया है। इसके अलावा ईबीआर और नकदी शेष के घटकों के साथ केंद्र सरकार के ऋण की परिभाषा को अप्रैल 2018 में एफआरबीएम संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था।

सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अतिरिक्त दायित्व, जो विशेष रूप से राज्य सरकार पर आती है (अर्थात, केंद्र सरकार के ऋणों को छोड़कर) 2020-21 तक बढ़ती प्रवृत्ति पर थी और उसके बाद 2021-22 के दौरान गिरावट आई। यह 20.14 प्रतिशत (2017-18) से बढ़कर 26.36 प्रतिशत (2020-21) हो गई और 2021-22 में घटकर 24.04 प्रतिशत हो गई।

## 2.2 गारंटी

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 276 के अनुसार, केंद्र सरकार मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं या गतिविधियों पर उधार लेने की लागत को कम करने के लिए सरकारी संस्थाओं को गारंटी देती है। संप्रभु गारंटी भी दी जाती है जहां यह द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता के लिए एक पूर्व शर्त है। आकस्मिक दायित्व होने के कारण गारंटियाँ ऋण का हिस्सा नहीं बनती हैं, लेकिन चूक की स्थिति में, उनका प्रभाव सरकार की दायित्वों पर पड़ सकता है।

एफआरबीएम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम यह निर्धारित करते हैं कि केन्द्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक भारत की समेकित निधि (सीएफआई) की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी।

मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण 2023-24 (फरवरी 2023) में सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटी 5.19 लाख करोड़ थी, लेकिन यह वित्तीय वर्ष 2004-05 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घटकर 2.19 प्रतिशत हो गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, अतिरिक्त गारंटी ₹0.96 लाख करोड़ या सकल घरेलू उत्पाद का 0.40 प्रतिशत थी, जो एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के तहत निर्धारित 0.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। **अनुलग्नक-2.1** अधिक जानकारी देता है। वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त गारंटी पिछले पांच वर्षों से सीमा के भीतर बनी हुई है। 2021-22 के दौरान जारी की गई अतिरिक्त गारंटियों (₹0.96 लाख करोड़ की) में से, अधिकांश वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय को ₹0.25 लाख करोड़ (कुल: 24) की श्रेणी-I गारंटी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ₹0.32 लाख करोड़ (कुल: 4) की श्रेणी-III

गारंटी और वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय को ₹0.22 लाख करोड़ (कुल: 7) की गारंटी थी।

### 2.3 अतिरिक्त बजटीय संसाधन

मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) 2019-20 में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की अवधारणा प्रस्तुत की, "वे वित्तीय देनदारियां जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाई गई थीं, जिनके लिए संपूर्ण मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान संघ सरकार के बजट से किया जाता है।" ये उधार केवल संबंधित संस्थाओं के लेखों में परिलक्षित होते हैं और न तो संबंधित मंत्रालय के अनुदान की मांग में दर्शाए जाते हैं और न ही वे वार्षिक वित्तीय विवरण (एफएस), केंद्र सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफ) और एफआरबीएम के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण विवरण में दिखाई देते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के बाद से, सरकार ने ईबीआर की राशि के बारे में प्रकटीकरण शुरू कर दिया था (बजट में व्यय प्रोफाइल का विवरण 27)। यह विवरण सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवा प्राप्त बांडों और राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाए गए ईबीआर को दर्शाता है।

वर्ष 2021-22 के लिए व्यय प्रोफाइल, 2023-24 (अनुलग्नक-2.2) के विवरण 27 में निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

i. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के तहत परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) की स्थापना की गई थी। हमें निम्नलिखित का पता चला:

- ❖ प्रकटीकरण में त्रुटि के कारण एलटीआईएफ के तहत जुटाई गई राशि (पोलावरम परियोजना के वित्तपोषण के लिए) को ₹9 करोड़ से अधिक बताया गया। मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया।
- ❖ एलटीआईएफ के तहत जुटाए गए कुल ₹55,438 करोड़ का ऋण नाबार्ड (64.8 प्रतिशत) और सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लिए अनुदान के अंतर्गत बजटीय सहायता (35.2 प्रतिशत) के माध्यम से चुकाया जाना था। जबकि सरकार ने मूल राशि के ₹1,445.43 करोड़ का भुगतान किया, लेकिन 31 मार्च 2022 तक

इस राशि को केंद्र सरकार के ऋण (₹138.65 लाख करोड़) से नहीं काटा गया, जिसके कारण केंद्र सरकार के ऋण को उसी राशि से अधिक बताया गया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2024)।

ii. भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी), सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय रेलवे की उधार लेने वाली शाखा है। यह रोलिंग स्टॉक और परियोजनाओं की खरीद के लिए बाजार<sup>15</sup> से ऋण लेता है जिसे यह भारतीय रेलवे (आईआर) को पट्टे पर देता है। बदले में आईआर और आईआरएफसी के बीच हस्ताक्षरित पट्टा समझौते की शर्तों के तहत, आईआर हर छह महीने में पट्टा किराये का अग्रिम भुगतान करता है। पट्टा किराया रेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक बजटीय सहायता के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

व्यय प्रोफाइल 2023-24 में रेलवे बजट पर सार के विवरण-I (प्राप्तियों और व्यय का अवलोकन) की प्राप्तियाँ (अतिरिक्त बजटीय संसाधन) और विवरण-III (रेलवे प्राप्तियों में) में आगे का ब्यौरा (क्रम संख्या 22 पर) से पता चला कि आईआर ने 2021-22 में ₹71,065.90 करोड़ के ईबीआर का उपयोग किया था। हालाँकि, इस राशि को केंद्रीय बजट 2023-24 के व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 में बाहर रखा गया था

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि सेवा के लिए सरकार से विशिष्ट और स्पष्ट प्रतिबद्धता वाले उधार को ईबीआर कहा जाता था; जबकि सीपीएसयू/वाणिज्यिक अधिकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से उनकी तुलन पत्र की ताकत के आधार पर पूल किए गए को आईईबीआर कहा जाता था। इसके अलावा, सरकार द्वारा अनुमत/सहमत ईबीआर का विवरण व्यय प्रोफाइल के विवरण संख्या 27 में प्रकटीकरण तंत्र के भाग के रूप में लाया गया था।

मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय रेलवे (आईआर) एक विभागीय रूप से संचालित वाणिज्यिक उपक्रम है, जो अपने परिचालन व्यय को कवर करने के लिए वाणिज्यिक संचालन के माध्यम से अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करता है। नतीजतन, आईआर के संसाधन, हालांकि सीएफआई (रेलवे राजस्व प्राप्तियाँ कहा जाता है) में जमा किए गए थे, भारत सरकार के अन्य सामान्य राजस्व से अलग थे और इसकी परिचालन आवश्यकताओं के लिए आईआर में वापस आ गए थे।

<sup>15</sup> इसके अलावा, आईआरएफसी ऋण के माध्यम से रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) की परियोजनाओं को भी वित्तपोषित करता है।

जबकि व्यय प्रोफाइल 2023-24 जिसमें रेलवे बजट पर सार शामिल है (विवरण-I के तहत - प्राप्तियों और व्यय का अवलोकन, और आगे विवरण-III के क्रम संख्या 22 में विस्तृत है - रेलवे प्राप्तियाँ), दर्शाता है कि आईआर ने 2021-22 में ₹71,065.90 करोड़ के ईबीआर (और आईईबीआर नहीं) का उपयोग किया था।

इस प्रकार, वित्त मंत्रालय आईआरएफसी की उधार ली गई राशि के वर्गीकरण और संघीय बजट में इसके प्रकटीकरण के संबंध में विचार कर सकता है।

## 2.4 वृहत आर्थिक मापदण्डों में प्रवृत्ति

- ❖ राजकोषीय घाटा, ऋण प्राप्तियों और ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान निधि में कुल प्राप्तियों पर भारत के समेकित कोष से कुल संवितरण की अधिकता को दर्शाता है।
- ❖ राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है।
- ❖ प्राथमिक घाटे का अर्थ है राजकोषीय घाटे को ब्याज भुगतान से घटाना।

## क. राजकोषीय संकेतक - रोलिंग लक्ष्य

### तालिका 2.4: वास्तविक की तुलना में अनुमान

(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

	एमटीएफपी 2019-20	एमटीएफपी 2020-21	एमटीएफपी 2021-22	एमटीएफपी 2022-23	यूजीएफए 2021-22
अनुमान राजकोषीय संकेतक का प्रकार	2021-22 के लिए अनुमान (वाई+2)	2021-22 के लिए अनुमान (वाई+1)	2021-22 के लिए बीई	2021-22 के लिए आरई	2021-22 के लिए वास्तविक
राजकोषीय घाटा	3.0	3.3	6.8	6.9	7.4
राजस्व घाटा	1.7	2.3	5.1	4.7	4.4
प्राथमिक घाटा	0.0	0.2	3.1	3.3	3.9
सकल कर राजस्व	11.6	10.7	9.9	10.8	11.4
गैर कर राजस्व	1.4	1.5	1.1	1.4	2.6
केंद्र सरकार का कर्ज	44.4 <sup>16</sup>	48.0	-	59.9	58.6
जिनमें से ईबीआर के कारण दायित्व हैं	0.9	0.9	2.9	0.6 <sup>17</sup>	0.6

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 जनवरी 2023 के अनुसार, वास्तविक 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद आंकड़े।

<sup>16</sup> कुल बकाया देनदारियां।

<sup>17</sup> व्यय प्रोफाइल 2022-23 के विवरण 27 से।

राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे का वास्तविक आंकड़ा बजटीय अनुमान से अधिक था जबकि राजस्व घाटा और केंद्र सरकार के ऋण का वास्तविक आंकड़ा कम था (तालिका 2.4)।

एमटीएफपी में मध्यम अवधि के अनुमानों के साथ वास्तविक संख्याओं के बीच भिन्नता के संबंध में, मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि अनुमान मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों पर आधारित थे। कुछ अंतर्निहित धारणाएँ ज्ञात-अज्ञात जोखिमों से प्रभावित होती हैं। हालाँकि, सरकार अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच इस अंतर को कम से कम करने का प्रयास कर रही है।

## ख . सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.)

तालिका 2.5: सकल घरेलू उत्पाद का उतार-चढ़ाव

(₹ लाख करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद)	170.90	189.00	200.75	198.01	236.65
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन (मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद)	11.03	10.59	6.22	-1.36	19.51
स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद)	131.45	139.93	145.16	135.58	147.36
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता परिवर्तन (स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद)	6.80	6.45	3.74	-6.60	8.68

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी 2022 और 06 जनवरी 2023।

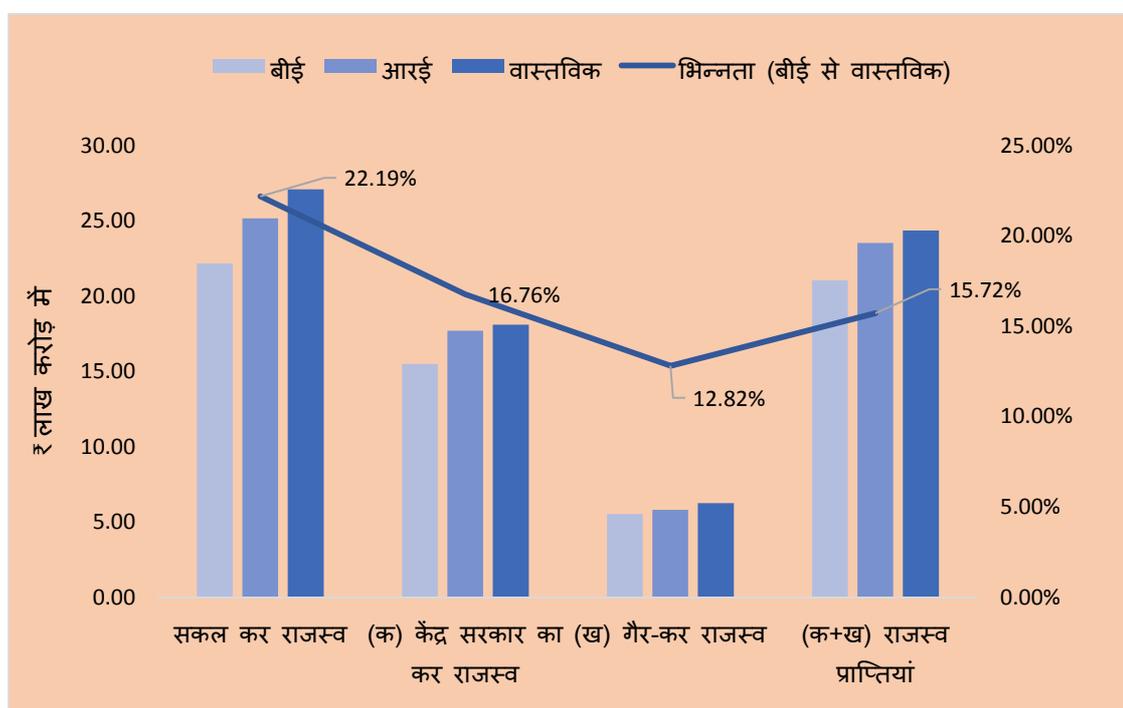
2020-21 के मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपी) में 2021-22 की सकल घरेलू उत्पाद नाममात्र के संदर्भ में ₹253.15 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। बजट 2021-22 में अनुमान लगाया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष

की तुलना में 14.4 प्रतिशत बढ़ेगा और 2021-22 में ₹222.87 लाख करोड़ का स्तर प्राप्त करेगा।

बजट 2022-23 में, 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर ₹232.15 लाख करोड़ कर दिया गया। हालाँकि, 2021-22 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इन अनुमानों से बढ़कर ₹236.65 लाख करोड़ हो गया।

## ग. राजस्व प्राप्तियाँ

ग्राफ 2.6: राजस्व प्राप्ति के अनुमानों की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण



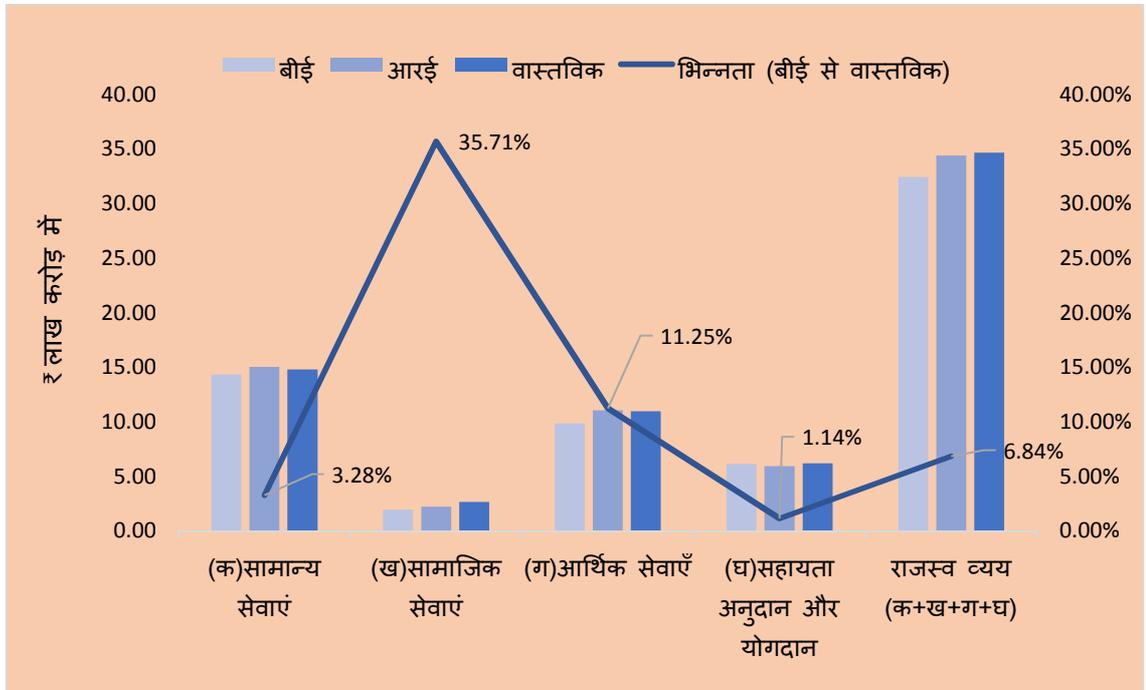
स्रोत: बीई के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2021-22 और वास्तविक के लिए यूजीएफए 2021-22।

राजस्व प्राप्तियों के मजबूत संग्रह से ₹27.09 लाख करोड़ का सकल कर राजस्व संग्रह हुआ, यानी बजट में अनुमानित राशि से 22.19 प्रतिशत अधिक। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजटीय ₹21.05 लाख करोड़ के प्रति कुल राजस्व प्राप्ति संग्रह ₹24.36 लाख करोड़ था। सभी सकल राजस्व घटकों में वृद्धि दर्ज की गई। इसमें गैर-कर राजस्व भी शामिल है, जो ₹6.25 लाख करोड़ के साथ बजट आंकड़े से 12.82 प्रतिशत अधिक है (अनुलग्नक-2.3)। हालाँकि, गैर-कर राजस्व के 'अन्य गैर-कर राजस्व' घटक के तहत मामूली गिरावट देखी गई, जहाँ 'भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइनें - राजस्व प्राप्ति' अनुमान से 12.1 प्रतिशत कम रहीं।

## घ. राजस्व व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व व्यय ₹34.68 लाख करोड़ था, जो बजट अनुमान से 6.84 प्रतिशत अधिक है (ग्राफ़ 2.7)। सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल राजस्व व्यय का 42.7 प्रतिशत था और बजट अनुमान (3.3 प्रतिशत अधिक) के करीब रहा। बजटीय अनुमानों का समान पालन आर्थिक सेवाओं में देखा गया। 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' और 'आवास' के लिए आवंटन में वृद्धि के कारण, सामाजिक सेवाओं के व्यय में वृद्धि देखी गई। सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक व्यय ₹2.66 लाख करोड़ बजट अनुमान से 35.7 प्रतिशत अधिक था (अनुलग्नक-2.4)।

ग्राफ़ 2.7: राजस्व व्यय के अनुमान की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण



स्रोत: बीई के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2021-22 और वास्तविक के लिए यूजीएफए 2021-22।

मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) 2021-22 में सरकार ने कहा कि आगामी वर्ष में सरकार का मुख्य ध्यान पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ाना होगा और फोकस क्षेत्र स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और जल संरक्षण बने रहेंगे।

तालिका 2.8: फोकस क्षेत्रों पर राजस्व व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पूँजीगत परिसंपत्ति के निर्माण हेतु अनुदान	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	खाद्य संग्रहण और भण्डारण	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	मृदा एवं जल संरक्षण	फोकस क्षेत्र पर कुल व्यय	राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में फोकस क्षेत्र पर व्यय
2019-20	1,87,342 (-2.1)	29,432 (26.2)	1,14,678 (6.8)	1,050 (280.3)	33 (-2.1)	3,32,535	26,15,320	12.73
2020-21	2,22,391 (18.7)	33,884 (15.1)	5,55,154 (384.1)	1,297 (23.4)	35 (4.9)	8,12,761	33,14,852	24.52
2021-22	2,42,646 (9.1)	70,236 (107.3)	3,02,620 (-45.5)	37,733 (2810.2)	33 (-3.4)	6,53,268	34,68,189	18.83

स्रोत: संबंधित वर्षों का यूजीएफए। कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी को दर्शाता है।

हमने देखा कि वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए 'पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान', 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण', और 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' शीर्ष के तहत व्यय में वृद्धि हुई, जबकि 'खाद्य भंडारण और भंडारण' और 'मृदा और जल संरक्षण' के तहत इसमें कमी आई। यद्यपि फोकस क्षेत्रों पर खर्च की गई राशि हर साल पूर्ण रूप से बढ़ रही थी, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 'फोकस क्षेत्रों पर व्यय' का हिस्सा 2021-22 के दौरान 2020-21 में 24.52 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 18.83 प्रतिशत हो गया। 2020-21 के दौरान खाद्य संग्रहण और भंडारण पर उच्च व्यय भारतीय खाद्य निगम की बकाया भुगतान के कारण था।

## ड. राजस्व और पूंजीगत व्यय

तालिका 2.9: राजस्व और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण

(₹ लाख करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	कुल व्यय
2017-18	21.40	3.25	0.82	25.47
	84.02 प्रतिशत	12.76 प्रतिशत	3.22 प्रतिशत	
2018-19	22.62	4.00	0.55	27.16
	83.28 प्रतिशत	14.69 प्रतिशत	2.03 प्रतिशत	
2019-20	26.15	3.88	0.45	30.48
	85.79 प्रतिशत	12.73 प्रतिशत	1.48 प्रतिशत	
2020-21	33.15	3.43	2.50	39.08
	84.83 प्रतिशत	8.78 प्रतिशत	6.39 प्रतिशत	
2021-22	34.68	5.38	2.32	42.39
	81.83 प्रतिशत	12.69 प्रतिशत	5.48 प्रतिशत	

स्रोत: संबंधित वर्षों का यूजीएफए। प्रतिशत में आंकड़े उस वर्ष के कुल व्यय के अनुपात के रूप में दिखाए जाते हैं।

राजस्व व्यय पूर्ण रूप से कुल व्यय के विस्तार के अनुरूप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कुल व्यय के अनुपात के रूप में, 2019-20 के अपवाद के साथ 2017-18 से 2021-22 की अवधि में इसमें गिरावट आई है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹3.43 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹5.38 लाख करोड़ (56.9 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया। इस वृद्धि का मुख्य घटक आर्थिक सेवाओं (₹1.82 लाख करोड़) में था, जो बदले में भारतीय रेलवे (₹0.87 लाख करोड़), नागरिक उड्डयन (₹0.62 लाख करोड़) और सड़कों और पुलों (₹0.25 लाख करोड़) पर बढ़े हुए व्यय के कारण था। 2021-22 के दौरान (32.7 प्रतिशत तक) समान वृद्धि 'सामाजिक सेवाओं' पर पूंजीगत व्यय में शहरी विकास पर उच्च व्यय पर थी, और 'सामान्य सेवाओं' में (7.8 प्रतिशत तक) रक्षा सेवाओं, मुद्रा, सिक्के और टकसाल एवं पुलिस पर थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान ऋण और अग्रिम के व्यय में जीएसटी मुआवजे की कमी<sup>18</sup> के एवज में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए बैंक-टू-बैंक ऋण की व्यवस्था शामिल थी, जिसमें 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹1.10 लाख करोड़ और ₹1.59 लाख करोड़ शामिल थे।

<sup>18</sup> 1जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था में स्थानांतरित होने पर कमी, यदि कोई हो, के लिए राज्य सरकारों को भारत सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना था। जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले में, भारत सरकार ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹1.10 लाख करोड़ और ₹1.59 लाख करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण का विस्तार करने का निर्णय लिया, जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा और भविष्य के मुआवजा उपकर संग्रह से वसूल किया जाएगा।

### च. पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में गैर-ऋण प्राप्तियां और ऋण प्राप्तियां शामिल होती हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (एनडीसीआर) के दो प्रमुख घटक हैं अर्थात् ऋणों और अग्रिमों तथा अन्य प्राप्तियों की वसूली (जिसमें अधिकतर विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं, जो रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री के अलावा सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी की बिक्री से सरकार को प्राप्त होती हैं)। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (एनडीसीआर) के प्रमुख हिस्से में परिसंपत्तियों की रणनीतिक बिक्री सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिस्सेदारी बिक्री के कारण विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं। बीई 2021-22 में अनुमान लगाया गया था कि विनिवेश से ₹1.75 लाख करोड़ की राशि एकत्र की जा सकती है, लेकिन वास्तव में केवल ₹0.15 लाख करोड़ ही एकत्र किए गए थे। इन वास्तविक प्राप्तियों में से, सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों<sup>19</sup> में अपनी इक्विटी के विनिवेश से ₹0.08 लाख करोड़ प्राप्त हुए।

### छ. गैर-ऋण प्राप्तियों से वित्तपोषित कुल व्यय

तालिका 2.10: गैर-ऋण प्राप्तियों और कुल व्यय का वर्षवार संग्रह

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (₹ लाख करोड़ में)	कुल व्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	गैर-ऋण प्राप्तियाँ (₹ लाख करोड़ में)*	गैर-ऋण प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय (प्रतिशत में)
2017-18	25.47	13.55	18.62	9.21	73.11
2018-19	27.16	6.64	19.32	3.76	71.13
2019-20	30.48	12.22	20.17	4.40	66.17
2020-21	39.08	28.22	19.32	-4.21	49.44
2021-22	42.39	8.47	24.76	28.16	58.41

स्रोत: संबंधित वर्षों का यूजीएफए।

\*गैर-ऋण प्राप्तियों में शामिल हैं - राजस्व प्राप्ति, विविध पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण और अग्रिम की वसूली।

महामारी पूर्व वर्षों (2018-19 और 2019-20) के दौरान गैर-ऋण प्राप्तियाँ साल दर साल लगभग 4 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी, और 2020-21 में 4 प्रतिशत से अधिक के संकुचन के बाद, 2021-22 के दौरान 28.16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। हमने

<sup>19</sup> राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (₹3,654 करोड़), आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (₹720 करोड़), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (₹742 करोड़) के हिस्से की बिक्री; एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश (₹2,700 करोड़); स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अब आरआईएल) के शेयरों की बिक्री (₹219 करोड़) और मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों की वापस खरीद (₹394 करोड़)।

देखा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 को छोड़कर, कुल व्यय में वर्ष-दर-वर्ष (वाईओवाई) वृद्धि गैर-ऋण प्राप्तियों में *प्रतिशत* (वाईओवाई) वृद्धि से कहीं अधिक है। यह कुल व्यय के वित्तपोषण के लिए ऋण प्राप्तियों की बढ़ती प्रवृत्ति में परिलक्षित होता है, जो महामारी-पूर्व अवधि (वित्तीय वर्ष 2020-21, एक गैर-मानक वर्ष होने के नाते) के दौरान की प्रवृत्ति से ऊपर है।

## 2.5 राजकोषीय घाटा

अप्रैल 2018 में संशोधन के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ एफआरबीएम अधिनियम 2003 में राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2021 तक ही निर्धारित किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए अधिनियम के तहत वर्ष के अंत का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में आश्वासन दिया गया कि "सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद स्तर 4.5 *प्रतिशत* से कम रखने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक रास्ते पर कायम रहेगी" जिसे 2022-23 के लिए मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) में दोहराया गया था।

राजकोषीय घाटे की हमारी गणना (तालिका 2.11) संघ सरकार के वित्त लेखों (यूजीएफए) से ली गई है।

तालिका 2.11: राजकोषीय घाटे की गणना

क्र.सं.	विवरण	मात्रा (₹ लाख करोड़ में)
1	यूजीएफए के अनुसार गैर-ऋण प्राप्तियाँ	24.76
	<i>राजस्व प्राप्तियाँ</i>	24.36
	<i>विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ</i>	0.15
	<i>ऋण एवं अग्रिम की वसूली</i>	0.25
2	यूजीएफए के अनुसार कुल संवितरण (ऋण चुकौती को छोड़कर)।	42.39
	<i>राजस्व व्यय</i>	34.68
	<i>पूंजीगत व्यय</i>	5.38
	<i>ऋण और अग्रिम</i>	2.32
3	यूजीएफए के अनुसार राजकोषीय घाटा (2-1)	17.63
	सकल घरेलू उत्पाद के <i>प्रतिशत</i> के रूप में	7.45
4	बजट सार (बीएजी) के अनुसार राजकोषीय घाटा	15.85
	सकल घरेलू उत्पाद के <i>प्रतिशत</i> के रूप में	6.70

स्रोत: राजकोषीय घाटे के लिए यूजीएफए 2021-22 का विवरण संख्या 1, बीएजी 2023-24 और सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 जनवरी 2023। (₹236.65 लाख करोड़)

यूजीएफए और बीएजी के बीच राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में अंतर यूजीएफए में कुछ लेनदेन को शामिल करने के कारण है, जैसे जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण, राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियां।

लेखापरीक्षा के उदाहरण पर, मंत्रालय ने बीएजी 2023-24 में एक सामान्य प्रकटीकरण शामिल किया, जिसमें कहा गया था कि "इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई प्राप्तियां और व्यय, प्राप्त और वसूलियों को छोड़कर हैं, जैसा कि रसीद बजट (अनुलग्नक -3) और व्यय प्रोफाइल दस्तावेज़ (विवरण संख्या 17)" में दिए गए समाधान विवरणों में बताया गया है। हालाँकि, स्पष्टीकरण में बीएजी में एफडी की गणना से उपरोक्त लेनदेन को शामिल न करने के आधार का विवरण देने की आवश्यकता है।

## 2.6 उधार - लोक ऋण और अन्य दायित्व

2021-22 के लिए कुल उधार आवश्यकता का बजट 2021-22 में ₹15.06 लाख करोड़ था। जिसमें से दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल उधार क्रमशः ₹12.05 लाख करोड़ और ₹9.17 लाख करोड़ की योजना बनाई गई थी। मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण 2022-23 में, मंत्रालय ने कहा कि "एनएसएसएफ के तहत उपलब्ध उच्च निवेश योग्य राशि के कारण, उपलब्ध नकदी शेष आदि के प्रभावी उपयोग के साथ, केंद्र सरकार के वित्त का प्रबंधन करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल उधार लेना आवश्यक है। आरई 2021-22 में क्रमशः ₹10.47 लाख करोड़ और ₹7.76 लाख करोड़ को तर्कसंगत बनाया गया है। हालाँकि, यूजीएफए के अनुसार<sup>20</sup> 2021-22 में ₹17.63 लाख करोड़ का घाटा आंतरिक ऋण से ₹15.53 लाख करोड़, बाहरी ऋण से ₹0.51 लाख करोड़ और लोक लेखा से ₹1.56 लाख करोड़ की उधारी के माध्यम से पूरा किया गया था इसमें, ₹0.03 लाख करोड़ की नकद निकासी हुई।

<sup>20</sup> संघ सरकार वित्त लेखा।

## 2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण (डी. एस. ए.) एक निश्चित अवधि के दौरान अपने ऋण संबंधी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की सरकार की क्षमता का आकलन करने का एक उपाय है। करने का एक उपाय है। विश्लेषण की आधारशिला ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात है। आधार यह है कि ऋण में वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि (सकल घरेलू उत्पाद-सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मापी गई) के अनुरूप होनी चाहिए। एक स्थायी राजकोषीय नीति वह है जहां ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात लंबी अवधि में स्थिर रहता है या घटता है।

**ऋण स्थिरीकरण संकेतक** एक उपयोगी संकेतक है। धारणा यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या सार्वजनिक उधार की लागत से अधिक हो जाती है, तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक घाटा कम हो जाए।

- ऋण स्थिरीकरण सूचक = क्वांटम प्रसार<sup>21</sup> + प्राथमिक घाटा<sup>22</sup>
- ऋण स्थिरता की स्थिति बताती है कि यदि:
  - ✓ ऋण स्थिरीकरण सूचक = 0, ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा।
  - ✓ ऋण स्थिरीकरण संकेतक नकारात्मक है, ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी।
  - ✓ ऋण स्थिरीकरण संकेतक सकारात्मक है, ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिर जाएगा।

2021-22 में ऋण स्थिरीकरण संकेतक सकारात्मक हो गया, जो स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेतक है (तालिका 2.12)

<sup>21</sup> क्वांटम स्प्रेड = केंद्र सरकार का ऋण x ब्याज स्प्रेड/100।

<sup>22</sup> प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान।

तालिका 2.12: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ लाख करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	केंद्र सरकार का ऋण	84.94	93.26	105.07	121.87	138.65
2	केंद्र सरकार के ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.74	9.80	12.66	15.99	13.77
3	मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद	170.90	189.00	200.75	198.01	236.65
4	मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.59	6.22	-1.36	19.51
5	ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत में)	49.70	49.34	52.34	61.55	58.59
6	ऋण पर चुकाया गया ब्याज	5.44	5.96	6.55	7.21	8.28
7	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	16.91	18.06	19.48	18.65	24.36
8	ऋण पर औसत ब्याज लागत (प्रतिशत में) <sup>23</sup>	6.73	6.69	6.61	6.35	6.36
9	राजस्व प्राप्ति पर ऋण पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	32.17	33.00	33.62	38.66	33.99
10	लोक ऋण चुकौती	58.73	60.65	63.27	61.85	66.45
11	लोक ऋण प्राप्ति	65.54	67.58	73.01	81.63	82.49
12	लोक ऋण चुकौती से लोक ऋण प्राप्ति (प्रतिशत में)	89.61	89.75	86.66	75.77	80.56
13	ब्याज प्रसार (प्रतिशत में) <sup>24</sup>	4.30	3.90	-0.39	-7.71	13.15
14	क्वांटम प्रसार <sup>25</sup>	3.65	3.64	-0.41	-9.40	18.23
15	प्राथमिक घाटा <sup>26</sup> (-)	1.42	1.89	3.76	12.54	9.34
16	ऋण स्थिरीकरण <sup>27</sup>	2.23	1.75	-4.17	-21.94	8.89

स्रोत: संबंधित वर्षों का यूजीएफए। सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31 जनवरी 2022 और 06 जनवरी 2023।

<sup>23</sup> औसत ब्याज लागत = ब्याज भुगतान / पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष का औसत बकाया ऋण x100

<sup>24</sup> ब्याज प्रसार = सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (वर्तमान मूल्य) - औसत ब्याज लागत।

<sup>25</sup> क्वांटम प्रसार = केंद्र सरकार का ऋण x ब्याज स्प्रेड/100।

<sup>26</sup> प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान।

<sup>27</sup> ऋण स्थिरीकरण = क्वांटम प्रसार + प्राथमिक घाटा।

आगे के विश्लेषण से निम्नलिखित पता चलता है:

- ❖ केंद्र सरकार का ऋण-से-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2017-18 में 49.70 प्रतिशत से बढ़कर 2020-2021 में 61.55 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गया। हालाँकि, 2021-2022 में अनुपात घटकर 58.59 प्रतिशत हो गया। अधिनियम के तहत लक्ष्य 40 प्रतिशत है, जिसे 2024-25 के अंत में प्राप्त किया जा सकता है।
- ❖ 2017-18 में लोक ऋण चुकौती और लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत 89.61 प्रतिशत था लेकिन 2021-22 में इसमें सुधार हुआ। नए लिए गए ऋण का 80.56 प्रतिशत ऋण चुकाया गया, जिससे उत्पादक व्यय के लिए उधारी समाप्त हो गई।
- ❖ राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज भुगतान सरकार के राजकोषीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह इस बात का माप है कि सरकार के राजस्व का कितना हिस्सा उसके ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अनुपात 2020-2021 में 38.66 प्रतिशत पर अपने चरम पर पहुंच गया और 2021-22 में गिरकर 33.99 प्रतिशत हो गया, जो एक सकारात्मक संकेत है।



# अध्याय 3

## प्रकटीकरण और पारदर्शिता



<b>अध्याय</b>	<b>प्रकटीकरण और पारदर्शिता</b>
<b>3</b>	

### 3.1 प्रकटीकरण विवरण

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 (संशोधित) की धारा 6 (1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान की मांग की तैयारी में गोपनीयता को यथासंभव कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। समय-समय पर संशोधित एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 6 में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान की मांग प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप में खुलासे (डी-1 से डी-5) करेगी। इसके अलावा, निर्धारित राजकोषीय संकेतकों की गणना को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की संभावना वाले लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव का एफआरबीएम नियमों के तहत खुलासा किया जाना भी आवश्यक है।

**तालिका 3.1: एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण विवरण**

प्रकटीकरण विवरण का शीर्षक	
डी1	राजस्व कर जुटाया किंतु वसूला नहीं गया
डी2	गैर-कर राजस्व का बकाया
डी3	सरकार द्वारा दी गई गारंटी
डी4	परिसंपत्ति रजिस्टर
डी5	वार्षिक परियोजनाओं पर देयता

#### 3.1.1 राजस्व कर जुटाया किंतु वसूला नहीं गया पर प्रकटीकरण फॉर्म 1 (डी1)

प्रकटीकरण विवरण 1 में जुटाये गये कर राजस्व का विवरण दिया गया है लेकिन वसूला नहीं गया अर्थात् संग्रहीत नहीं किया गया। फिर इन्हें 'विवादाधीन' और 'विवादाधीन नहीं'

मदों की अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹15.83 लाख करोड़ की राशि जुटाई गई लेकिन वसूल नहीं की गई, जो कुल एकत्रित कर का 58.42 प्रतिशत है। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ₹16.19 लाख करोड़ के संबंधित आंकड़े से एक सुधार था, जो कुल एकत्रित कर का 68.81 प्रतिशत था।

विवरण में, ₹12.03 लाख करोड़ को 'विवादाधीन' के रूप में दर्शाया गया, जिसमें से ₹10.36 लाख करोड़<sup>28</sup> आयकर से संबंधित थे और शेष ₹1.67 लाख करोड़ वस्तुओं और सेवाओं पर कर से संबंधित थे। हमारे विश्लेषण से पता चला कि ₹0.35 लाख करोड़ जो 'विवादाधीन' मद के अंतर्गत परिलक्षित हुए थे, तथा ये 10 वर्षों से अधिक की अवधि से संबंधित थे। आयकर में पांच वर्ष से अधिक समय से विवादित मामलों की लंबितता 2020-22 के दौरान ₹0.59 लाख करोड़ से बढ़कर ₹0.62 लाख करोड़ और वस्तुओं और सेवाओं पर कर के संबंध में ₹0.53 लाख करोड़ से बढ़कर ₹0.62 लाख करोड़ हो गई।

₹3.80 लाख करोड़ की राशि, जो 'विवाद के अधीन नहीं' थी, में आयकर पर ₹3.54 लाख करोड़ और शेष ₹0.25 लाख करोड़ वस्तुओं और सेवाओं पर कर शामिल थे, जिन्हें अभी वसूल किया जाना था। आयकर में 'विवादाधीन नहीं' राशि की पाँच वर्षों से अधिक की लंबितता (₹0.17 लाख करोड़ से ₹0.16 लाख करोड़) कम हो गई लेकिन वस्तुओं और सेवाओं पर कर के तहत वृद्धि दर्ज की गई (₹0.12 लाख करोड़ से ₹0.13 लाख करोड़)। प्रकटीकरण विवरण में गैर-वसूली के लिए "कोई परिसंपत्ति नहीं या वसूली के लिए अपर्याप्त परिसंपत्ति, जो अनुरेखणीय न हो परिसंपत्ति आदि" को जिम्मेदार ठहराया गया है।

### 3.1.2 आंकड़ों में विसंगतियाँ

गैर-कर राजस्व (एनटीआर) के बकाया का विवरण फॉर्म डी2 में बताया गया है। पिछली सीएजी प्रतिवेदनों<sup>29</sup> ने उस वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे (विवरण 15) में बताए गए आंकड़ों की तुलना में फॉर्म डी-2 में ब्याज प्राप्तियों<sup>30</sup> में बकाया के रूप में

<sup>28</sup> ₹10.36 लाख करोड़ में से ₹4.78 लाख करोड़ की राशि निगम कर से संबंधित है, और ₹5.58 लाख करोड़ निगम कर के अलावा आय पर कर से संबंधित है।

<sup>29</sup> 2021 की प्रतिवेदन संख्या 6 (2017-19 की अवधि के लिए), 2022 की प्रतिवेदन संख्या 18 (2019-20 की अवधि के लिए) और 2022 की प्रतिवेदन संख्या 32 (2020-21 की अवधि के लिए)।

<sup>30</sup> राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों में बकाया।

प्रकट किए गए वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर बताया है। अंतर बरकरार है जैसा कि तालिका 3.2 में दिखाया गया है।

**तालिका 3.2: ब्याज प्राप्तियों के बकाया में असंगतता**

(₹ लाख करोड़ में)

ऋणी इकाई	ब्याज की बकाया राशि		भिन्नता
	जैसा कि डी2 में है (प्राप्ति बजट 2023-24)	जैसा कि यूजीएफए 2021-22 में है	
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार	0.03	0.05	0.02
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	0.39	0.42	0.03

स्रोत: प्राप्ति बजट 2023-24 और संघ सरकार के वित्त लेखे 2021-22।

हमने नोट किया कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग बकाया का राज्य-वार विवरण तैयार करते हैं जो विवरण 15 खंड 2 में समेकित हैं। वित्त मंत्रालय के तहत संघीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) की ऑनलाइन उपयोगिता व्यक्तिगत मंत्रालयों से प्रतिक्रियाओं का एक समेकन है। एक सामान्य पैरामीटर यानी राज्य-वार जानकारी के अभाव में डेटा के इन दो सेट का समाधान नहीं हो सका।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि विवरण तैयार करने की प्रक्रिया यूजीएफए के मामले में अपनाई गई प्रक्रिया से काफी अलग है। एफआरबीएम अनुभाग इस उद्देश्य के लिए अपनी यूबीआईएस सुविधा पर सभी मंत्रालयों/विभागों से जानकारी प्राप्त करता है। यूजीएफए के संकलन की प्रक्रिया में समय लगता है और समय पर समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह आम तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं होता है। इसके अलावा, हमें आश्वासन दिया गया कि सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालाँकि लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट की गई थी।

हमने देखा कि लेखों को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय में अंतिम रूप दिया जाता है, जिसके पास सीजीए द्वारा तैयार किए गए मासिक लेख भी उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूबीआईएस में दर्ज किया गया डेटा, विशेष रूप से "फॉर्म डी-2 में 'राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार'

और 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों' से लंबित ब्याज प्राप्तियां", यूजीएफए के अनुसार मेल खाता है।

फॉर्म डी-4 में दर्शायी गई वित्तीय परिसंपत्ति (तालिका 3.3) के संबंध में विसंगतियों के लिए मंत्रालय द्वारा इसी तरह के कारणों का हवाला दिया गया था। हमने प्राप्त बजट 2023-24 के विवरण संख्या 1(ii) में दिए गए आंकड़ों की तुलना में ऋण और अग्रिम के तहत ₹4.87 लाख करोड़ का महत्वपूर्ण अंतर देखा।

**तालिका 3.3: वित्तीय परिसंपत्तियों (ऋण और अग्रिम) के आंकड़ों में असंगतता**

(₹ लाख करोड़ में)

सामान	फॉर्म डी-4 (परिसंपत्ति रजिस्टर) प्राप्त बजट 2023-24 में	प्राप्ति बजट 2023-24 का विवरण संख्या 1(ii) और यूजीएफए 2021-22	अंतर
विदेशी सरकारों को ऋण	0.16	0.15	0.01
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण	0.05	4.92	4.87

स्रोत: प्राप्ति बजट 2023-24 और संघ सरकार के वित्त लेखे 2021-22।

मंत्रालय ने आगे आश्वासन दिया (अक्टूबर 2023) कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से काफी बदलाव के साथ मंत्रालयों/विभागों के संबंध में एक फुटनोट शामिल किया गया है।

### 3.1.3 प्रकटीकरण में चूक

भारत सरकार ने ₹9,495 करोड़ की एकल डिफॉल्ट गारंटी जारी की (दिनांक 29.06.2020 को खाद्य गारंटी में ₹500 करोड़ की दाल गारंटी के विलय के बाद) जो नवीनीकरण पर 31.03.2022 तक वैध थी। डी-3 फुटनोट में 'सरकार द्वारा दी गई गारंटी' में इसका खुलासा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2023), मंत्रालय ने बताया कि "खाद्य और लोक वितरण विभाग को फॉर्म डी 3 के अनुसार गारंटी के प्रकटीकरण विवरण में फुटनोट के तहत गारंटी के नवीनीकरण के विवरण का खुलासा करने की सलाह दी गई है।

हमने आगे देखा कि वर्ष के दौरान ₹1770.84 करोड़ (नौ गारंटियों के संबंध में) की राशि की मांग की गई थी और वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा "डिस्चार्ज" के रूप

में दिखाया गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि वित्तीय सेवा विभाग को फॉर्म डी 3 के अनुसार गारंटी के प्रकटीकरण विवरण में फुटनोट के तहत गारंटी की मांग के विवरण का खुलासा करने की सलाह दी गई है।

### 3.1.4 फॉर्म डी5 में विवरण के प्रकटीकरण में भिन्नता

एफआरबीएम नियम 2004 के नियम 6(1)(सी) के अनुसार, केंद्र सरकार स्पष्ट आकस्मिक दायित्वों के विवरण का खुलासा करेगी, जो फॉर्म डी-5 में बहु-वर्षीय समय सीमा में निर्धारित वार्षिक भुगतान के रूप में हैं।

हमने ध्यान दिया कि गृह मंत्रालय के तहत "जय सिंह रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास" परियोजना के संबंध में, प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी ₹1,178.80 करोड़ बताई गई थी। हालाँकि, 13 वर्षों (वर्षों की संख्या) के लिए भुगतान की जाने वाली आवश्यक ₹78 करोड़ की वार्षिक वार्षिकी राशि के आधार पर, गणना मूल्य ₹1,014 करोड़ (अर्थात्, 13x78) आता है जैसा कि तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: फॉर्म डी5 में विवरण में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना का मूल्य	प्रतिबद्ध कुल वार्षिकी	शर्तें वर्षों में	वार्षिक वार्षिकी	गणना के अनुसार वार्षिक वार्षिकी	भिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) x (6)	(8) = (4) - (7)
गृह मंत्रालय	जय सिंह रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	286.0	1178.8	13	78	1,014	164.8

स्रोत: प्राप्ति बजट 2023-24।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने आंकड़ों का मिलान प्रस्तुत किया और कहा कि भिन्नता दो किस्तों (₹80.80 करोड़) के पूर्व भुगतान और परियोजना के दायरे में बदलाव के लिए ₹84 करोड़ की राशि के एकमुश्त भुगतान के कारण थी। हम अनुशंसा करते हैं कि इस तरह के मिलान कार्य को भविष्य में प्रकटीकरण विवरण में दर्शाया जाना चाहिए। मंत्रालय ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2023) कि गृह मंत्रालय को सलाह दी गई है कि वह फुटनोट के तहत फॉर्म डी5 के अनुसार वार्षिक परियोजनाओं पर देयता विवरण में वार्षिकी के संबंध में इस तरह के एकमुश्त भुगतान का खुलासा करे।

नई दिल्ली

दिनांक: 21 मार्च 2024



(रोली शुक्ला माल्गे)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 22 मार्च 2024



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

**अनुलग्नक**



## अनुलग्नक-1.1

(पैरा 1.1 देखें)

## एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण

2003 में उनके पहले अधिनियमन के बाद से

(आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	लक्ष्य विवरण	प्रमुख अधिनियम/नियम	पहला संशोधन (2004 में)	दूसरा संशोधन (2012 में)	तीसरा संशोधन (2015 में)	चौथा संशोधन (2018 में)
1. राजस्व घाटा <sup>31</sup>	लक्ष्य	शून्य	शून्य	2	2	कोई लक्ष्य नहीं
	वार्षिक कटौती	0.5	0.5	0.6	0.4	
	वित्तीय वर्ष की शुरुआत	2004-05	2004-05	2013-14	2015-16	
	अंतिम तिथि	31.03.08	31.03.09	31.03.15	31.03.18	
2. राजकोषीय घाटा <sup>32</sup>	लक्ष्य	3	3	3	3	3
	वार्षिक कटौती	0.3	0.3	0.5	0.4	0.1
	वित्तीय वर्ष की शुरुआत	2004-05	2004-05	2013-14	2015-16	2018-19
	अंतिम तिथि	31.03.08	31.03.09	31.03.17	31.03.18	31.03.21
3. गारंटी <sup>33</sup>	2004-05 से शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल गारंटी सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए					किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से

<sup>31</sup> नियम 2(सीए) राजस्व घाटे को राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित करता है।

<sup>32</sup> धारा 2(ए) राजकोषीय घाटे को एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि से, ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर, निधि में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) से अधिक के रूप में परिभाषित करती है।

<sup>33</sup> अप्रैल 2018 में संशोधित एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4 (1) एक वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त गारंटी की सीमा निर्दिष्ट करती है, जो संशोधन से पहले वर्ष के अंत में कुल गारंटी को लक्षित करता था।

राजकोषीय संकेतक	लक्ष्य विवरण	प्रमुख अधिनियम/नियम	पहला संशोधन (2004 में)	दूसरा संशोधन (2012 में)	तीसरा संशोधन (2015 में)	चौथा संशोधन (2018 में)
						अधिक भारत की समेकित निधि की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के लिए कोई अतिरिक्त गारंटी नहीं
4.	देयता/ ऋण	प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देनदारियां (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) नहीं लेना और प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक प्रतिशत अंक तक कम करना।				2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण और केंद्र सरकार का ऋण क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

## अनुलग्नक-1.2

(पैरा 1.1 देखें)

## वित्त मंत्रालय द्वारा मध्य-वर्ष समीक्षा के परिणाम

(₹ लाख करोड़ में)

पैरामीटर	2021-22 का लक्ष्य	2021-22 के दौरान वास्तविक
<b>गैर-ऋण प्राप्तियां</b>		
गैर-ऋण प्राप्तियां (बीई - ₹ 19.76)	₹7.90	₹10.99
मध्य वर्ष बेंचमार्क (बीई के प्रतिशत के रूप में)	40 प्रतिशत से कम नहीं	55.60 % (कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं)
<b>राजस्व घाटा</b>		
राजस्व घाटा (बीई - ₹ 11.41)	₹7.98	₹3.16
मध्य वर्ष बेंचमार्क (बीई के प्रतिशत के रूप में)	70 प्रतिशत से अधिक नहीं	27.70 % (कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं)
<b>राजकोषीय घाटा</b>		
राजकोषीय घाटा (बीई - ₹ 15.07)	₹10.55	₹5.27
मध्य वर्ष बेंचमार्क (बीई के प्रतिशत के रूप में)	70 प्रतिशत से अधिक नहीं	35.00 % (कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं)

स्रोत: 2021-22 के लिए मध्य-वर्ष बेंचमार्क के प्रति वास्तविक आंकड़ों के लिए मध्य-वर्ष (एच1) विवरण।

अनुलग्नक-2.1  
(पैरा 2.2 देखें)  
गारंटी का विवरण

(₹ लाख करोड़ में)

क्र. सं.	अवयव	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	वर्ष के दौरान अधिकतम राशि की गारंटी	4.32	4.59	5.10	5.34	5.93
2	वर्ष की शुरुआत में बकाया	3.66	3.81	4.50	4.70	4.98
3	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	0.66	0.78	0.61	0.64	0.96
4	हटाना (मांगी गई के अलावा)	0.52	0.11	0.44	0.36	0.72
5	वर्ष के दौरान मांगी गई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
6	समय गारंटी	0.14	0.67	0.17	0.28	0.22
7	वर्ष के अंत में बकाया	3.80	4.48	4.67	4.98	5.19
8	सकल घरेलू उत्पाद	170.90	189.00	200.75	198.01	236.65
9	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान गारंटी की अधिकतम राशि	2.53	2.43	2.54	2.69	2.51
10	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त गारंटी	0.38	0.41	0.30	0.32	0.40
11	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वर्ष के अंत में बकाया	2.14	2.01	2.24	2.37	2.10

स्रोत: संबंधित वर्षों का यूजीएफए

## अनुलग्नक-2.2

(पैरा 2.3 देखें)

## अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) का विवरण

(सरकार से पूरी तरह से सेवित बांड और अन्य संसाधन)

(केंद्रीय बजट 2023-24 के व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 से अपनाया गया)

## भाग-क - सरकार द्वारा पूर्ण सेवित बांड जारी करके जुटाई गई ईबीआर

मांग संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	2016-17 से 2021-22 तक संचयी राशि (₹ करोड़ में)
26	<b>उच्च शिक्षा विभाग</b>	
	शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना (आरआईएसई)	---
46	<b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</b>	
	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	---
60	<b>आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय</b>	
	प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी	20,000
62	<b>जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग</b>	
	(i) पोलावरम सिंचाई परियोजना	6,245
	(ii) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं अन्य परियोजनाएँ)	1,470.80
63	<b>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग</b>	
	(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	12,298.20
	(ii) जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	---
71	<b>नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>	शून्य
	(i) ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत, ऑफ-ग्रिड/वितरित एवं विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत	1,640
	(ii) प्रधानमंत्री -किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	---
78	<b>बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय</b>	
	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) परियोजनाएं	1,000

2024 की प्रतिवेदन संख्या 1

मांग संख्या	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	2016-17 से 2021-22 तक संचयी राशि (₹ करोड़ में)
79	<b>विद्युत मंत्रालय</b>	
	(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना /सौभाग्य	29,109
	(ii) पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट्स	5,504.70
87	<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>	
	प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण	48,819.60
	<b>कुल</b>	<b>1,39,287.30</b>

टिप्पणियाँ:

- ❖ (i) रेलवे मंत्रालय को अपनी राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उधार के माध्यम से ₹10,200 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹5,200 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹5,000 करोड़) तक की निधि आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। पुनर्भुगतान दायित्व सरकार के सामान्य राजस्व पर वहन किया जा रहा है।
- ❖ (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश: 2017-18 में ₹80,000 करोड़ की राशि, 2018-19 में ₹1,06,000 करोड़, 2019-20 में ₹65,443 करोड़, 2020-21 में ₹17,364 करोड़ और ₹4,600 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूँजीकरण के लिए 2021-22 में करोड़ रुपये का निवेश किया गया।
- ❖ (iii) वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता का विवरण प्राप्त बजट 2022-23 के भाग-बी में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में अवैतनिक वार्षिक देनदारी की राशि ₹39,927.66 करोड़ थी।

अनुलग्नक-2.3  
(पैरा 2.4 सी देखें)

राजस्व प्राप्ति के अनुमान के मुकाबले वास्तविक का विश्लेषण

(₹ लाख करोड़ में)

मद	बीई	आरई	वास्तविक	भिन्नता (बीई से वास्तविक) (प्रतिशत के रूप में)
सकल कर राजस्व	22.17	25.16	27.09	22.19
आय और व्यय पर कर	10.96	12.30	13.85	26.37
संपत्ति और पूंजी लेनदेन पर कर	0.13	0.20	0.23	76.92
जीएसटी के अलावा वस्तुओं और सेवाओं पर कर	4.72	5.84	5.95	26.06
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	6.33	6.78	7.02	10.90
(क) केंद्र सरकार का कर राजस्व	15.51	17.71	18.11	16.76
(ख) गैर-कर राजस्व	5.54	5.82	6.25	12.82
(क+ख) राजस्व प्राप्तियां	21.06	23.54	24.36	15.72

स्रोत: बीई के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2021-22, आरई के लिए 2022-23 और वास्तविक के लिए यूजीएफए 2021-22।

अनुलग्नक-2.4  
(पैरा 2.4 डी देखें)

राजस्व संवितरण के अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण

(₹ लाख करोड़ में)

मद		बीई	आरई	वास्तविक	भिन्नता (बीई से वास्तविक) (प्रतिशत के रूप में)
(क) सामान्य सेवाएं		14.35	15.05	14.82	3.28
(ख) सामाजिक सेवाएं		1.96	2.22	2.66	35.71
अधिक अंतर वाले शीर्ष	i. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	0.19	0.35	0.38	100
	ii. आवास	0.10	0.22	0.55	445
(ग) आर्थिक सेवाएँ		9.87	11.07	10.98	11.25
(घ) सहायता अनुदान और योगदान		6.15	5.95	6.22	1.14
राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)		32.46	34.43	34.68	6.84

स्रोत: बीई के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2021-22, आरई के लिए 2022-23 और वास्तविक के लिए यूजीएफए 2021-22।

\* कुल राजस्व व्यय के बीई और आरई में विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों का संवितरण भी शामिल है।

# शब्दकोष



## शब्दकोष

<b>वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)</b>	<p>संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा जाता है। प्राप्ति और संवितरण को तीन भागों के अंतर्गत दिखाया गया है जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, अर्थात् (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, और (iii) लोक लेखा।</p>
<b>बजट सार</b>	<p>यह दस्तावेज़ संक्षेप में, प्राप्तियों और संवितरण के साथ-साथ कर राजस्व, अन्य प्राप्तियों और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को हस्तांतरित संसाधनों के विस्तृत विवरण दिखाता है। यह दस्तावेज़ सरकार के घाटे को भी दर्शाता है।</p>
<b>भारत की समेकित निधि</b>	<p>भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने हेतु लिए गए सभी ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के चुकाने में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशि संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत स्थापित "भारत की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि बनेगी।</p>
<b>लोक लेखा</b>	<p>भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में जमा धन के अलावा अन्य सभी सार्वजनिक धन को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है। ये वे पैसे हैं जिनके संबंध में सरकार एक बैंकर के रूप में अधिक कार्य करती है।</p>
<b>वित्त लेखा</b>	<p>वित्त खाते राजस्व और पूंजीगत खातों, लोक ऋण के खातों और खातों में दर्ज शेष राशि से निकाली गई दायित्वों और परिसंपत्तियों द्वारा दर्शाए गए वित्तीय परिणामों के साथ प्राप्तियों और संवितरण के खातों को प्रस्तुत करते हैं।</p>

<p><b>राजकोषीय नीति</b></p>	<p>सरकार की राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व बढ़ाने और सरकारी व्यय करने से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय और संसाधन प्रबंधन जिम्मेदारियों का कितनी अच्छी तरह से निर्वहन किया गया है।</p>
<p><b>सकल घरेलू उत्पाद</b></p>	<p>सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमा में किसी विशेष समय अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है , जिसकी गणना आम तौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है। इसमें सभी निजी और सार्वजनिक उपभोग, सरकार के परिव्यय, निवेश और एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर होने वाले आयात को छोड़कर निर्यात शामिल हैं। जीडीपी की गणना निर्दिष्ट आधार वर्ष के संदर्भ में स्थिर कीमतों पर और मौजूदा कीमतों पर भी की जाती है (जिसमें मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में बदलाव या समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि शामिल है)।</p>
<p><b>गारंटी</b></p>	<p>संविधान का अनुच्छेद 292 संघ की कार्यकारी शक्ति को भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर ऐसी सीमाओं, यदि कोई हो, के भीतर गारंटी देने तक विस्तारित करता है, जो संसद द्वारा तय की जा सकती हैं।</p>
<p><b>राजस्व घाटा</b></p>	<p>राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय।</p>
<p><b>राजस्व व्यय</b></p>	<p>रखरखाव, मरम्मत और कामकाजी खर्चों पर शुल्क, जो परिसंपत्तियों चालू क्रम में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए खर्च, ऐसे अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार और अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदान को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही अनुदान का कुछ हिस्सा पूंजीगत परिसंपत्ति बनाने के लिए हो।</p>

<b>राजस्व प्राप्तियाँ</b>	इनमें सरकार द्वारा लगाए गए करों और शुल्कों की आय, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
<b>प्रभावी राजस्व घाटा</b>	प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसकी व्याख्या सरकार के वर्तमान व्यय (राजस्व लेखे पर) और राजस्व प्राप्तियों के बीच पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को घटाकर अंतर के रूप में की जा सकती है, जिसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।
<b>पूंजीगत व्यय</b>	पूंजीगत प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर भौतिक और स्थायी चरित्र की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने या आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है।
<b>पूंजीगत प्राप्ति</b>	पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा उठाए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार और विदेशी सरकारों/संस्थानों से लिए गए ऋण शामिल हैं। इसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली और सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री आय भी शामिल है, जिसमें पीएसयू में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय भी शामिल है।
<b>राजकोषीय घाटा</b>	एक वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत की समेकित निधि से कुल संवितरण की अधिकता में निधि में कुल प्राप्तियों पर ऋण की चुकौती तथा ऋण प्राप्तियों शामिल नहीं किया है।
<b>बाह्य ऋण</b>	सरकार द्वारा विदेशी सरकारों और विदेशों में वित्तीय संस्थानों से अनुबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण, ज्यादातर विदेशी मुद्रा में।
<b>आंतरिक ऋण</b>	आंतरिक ऋण में भारत में लिए गए ऋण शामिल हैं। यह उठाए गए ऋण और भारत की समेकित निधि में जमा किए जाने तक ही सीमित है।

<b>ऋण और अग्रिम</b>	इसमें संघ सरकार द्वारा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
<b>लोक ऋण</b>	भारत की समेकित निधि में अनुबंधित आंतरिक और बाह्य स्रोतों से प्राप्त सरकारी ऋण को लोक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है।



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)